Act are clubbed in one category, which includes foundations, voluntary organisations, hospitals, private schools, universities, etc. So, no differentiation is done either at the time of registration or while implementing the FCRA.

Recently, at one go, more than 4,000 registrations were cancelled without citing reasons to organisations or even indicated the same on the website of department.

In 2005, the Government of India drafted the National Policy of Voluntary Sector to promote genuine voluntary development organisations and streamlining their relationship with various departments of the Government of India.

Similarly, there is need to create a separate Ministry for voluntary sector and national law for registration not only to regulate the sector in professional way but also to strengthen genuine organisations working on many social and development issues.

Realizing these concerns, I urge upon the Government to have a regular dialogue with voluntary development sector and urgently address those issues mentioned above, particularly with those genuine organisations affected by the FCRA cancellation.

## Demand to set up a Helicopter manufacturing unit in Bidar District of Karnataka

**श्री बसावाराज पाटिल** (कर्णाटक): महोदय, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा कर्णाटक के बीदर जिले में हेलीकॉप्टर तैयार करने का एक घटक प्रारम्भ करने का प्रस्ताव कर्णाटक के प्रतिनिधिमंडल के सम्मुख रखा गया था। बीदर में भारतीय सेना का वायुसेना प्रशिक्षण केन्द्र होने के नाते वहां हेलीकॉप्टर घटक खोलना इस परिवार के लिए लाभदायक होगा।

आप वहां की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर तथा अन्य अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकता के अनुसार जमीन के लिए प्रस्ताव कर्णाटक सरकार को रखें, जो उत्तर कर्णाटक के विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध होगा। इस निमित्त मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वहां हेलीकॉप्टर घटक प्रारंभ करने की पहल शुरू करें तथा जो सलाह आपने प्रतिनिधिमंडल को दी थी, उसे शीघ्र लागू करें।

## Demand to take steps to improve the condition of quarters of Central Government Employees in Delhi

**श्री डी.पी. त्रिपाठी** (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए बनी सरकारी कालोनियों के मकानों की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, उच्च अधिकारियों और सांसदों के बंगलों की तो फिर भी थोड़ी बहुत देखभाल